माननीय सदस्यगण,

यह सुखद संयोग है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र रंगों के त्यौहार होली के बाद शुरू हो रहा है। फाल्गुनी आनंद के बीच बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का यह पर्व आपसी सद्भाव, समरसता और भाई–चारे का संदेश देता है। आप सभी को नव–वर्ष और होली की बधाइयां देते हुए यह कामना करता हूं कि हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह बेहतर ढंग से करने में सफल हों, लोकतंत्र और संसदीय जिम्मेदारियों के प्रति हमारे मजबूत संकल्प का लाभ प्रदेश और समाज के हर तबके को मिले।

2. राज्य के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार की नीतियों और योजनाओं के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वर्ष 2009–10 में जहां राज्य ने 11.49 प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का कीर्तिमान स्थापित किया था, वहीं वर्ष 2010–11 में छत्तीसगढ़ ने अपने ही पुराने कीर्तिमान को तोड़कर 11.57 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल की है।

3. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार की योजनाओं और किसान भाई– बहनों की मेहनत ने कृषि क्षेत्र में सफलता की अद्भुत कहानियां लिखी हैं। राज्य गठन से लेकर वर्ष 2010–11 तक विभिन्न फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ी है। धान (खरीफ) की उत्पादकता 1 हजार 646 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1 हजार 751, सोयाबीन की 798 से बढ़कर 1 हजार 192, गेहूं की 1 हजार 41 से बढ़कर 1 हजार 281, मक्का की 1 हजार 98 से बढ़कर 1 हजार 562, चना की 730 से बढ़कर 1 हजार 53 और गन्ना की 2 हजार 651 से बढ़कर 3 हजार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है।

4. सर्वाधिक धान उत्पादन के लिए इस वर्ष छत्तीसगढ़ को प्रथम बार 'कृषि कर्मण पुरस्कार' का गौरव मिला है। मेरी सरकार ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के साथ मानक बीजों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। 'अक्ति बीज संवर्धन योजना' से विगत 3 वर्षों में मानक बीजों का उत्पादन 255 प्रतिशत बढ़ा है। 'प्रामाणिक बीज उत्पादन अनुदान' राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और 'बीज क्रय अनुदान' राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।

5. देश में पहली बार मेरी सरकार ने 3 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण देने की शुरुआत की थी। गौ पालन, मछली पालन, उद्यानिकी के लिए भी यह सुविधा दी गई। इससे कृषि ऋण प्रदाय की राशि विगत 8 वर्षों में 150 करोड़ रुपए से बढ़कर 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लगभग डेढ़ लाख किसानों को इस वर्ष क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिससे अब लगभग 14 लाख किसानों को यह सुविधा मिलने लगी है। किसान हितकारी योजनाओं के बारे में गांवों में जागरूकता लाने के लिए 10 हजार 'किसान संगवारियों' की नियुक्ति के साथ ही उन्नत तकनीक की जानकारी तथा प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक 'अटल सूचना केन्द्र' स्थापित किया जा रहा है।

6. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान व उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाने हेतु मेरी सरकार आगामी सत्र से 'कामधेनु विश्वविद्यालय' प्रारंभ कर रही है। गौवंशीय पशुओं के संरक्षण हेतु 'छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004' को संशोधित कर कठोर बनाया गया है। 1 लाख 65 हजार

मछुआरों को बेहतर आय का जरिया सुलभ कराने के प्रयासों के साथ ही मेरी सरकार ने मछुआरों को 'दुर्घटना बीमा योजना' से भी लाभान्वित किया है। 'राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम' के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश के दो अग्रणी राज्यों में स्थान मिला है।

7. मेरी सरकार ने किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रेरित करने के साथ उन्हें मेहनत का सही दाम भी दिलाया है। खरीफ वर्ष 2011–12 में 59 लाख 63 हजार टन धान की खरीदी के नए कीर्तिमान से इस वर्ष किसानों को 6 हजार 500 करोड़ रुपए का भुगतान मिला है। सर्वाधिक धान खरीदने में छत्तीसगढ़, देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया है।

8. कृषि विकास के लिए जो व्यापक कार्य किए गए हैं, उन्हें अधिक परिणाममूलक बनाने के लिए मेरी सरकार पृथक से कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रही है। कृषि बजट बनाने वाले पहले दो राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल हो गया है। राज्य की नई कृषि नीति बनाने हेतु भी व्यापक विचार–विमर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है।

9. राज्य गठन के समय सिंचाई का प्रतिशत मात्र 22.94 था, जो अब बढ़कर 31.83 हो गया है। खरीफ फसल के दौरान निर्मित सिंचाई क्षमता का वास्तविक उपयोग 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 71 प्रतिशत हो गया है। वर्षों से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने की एक मिसाल 'केलो जलाशय वृहद परियोजना' भी है, जिसका निर्माण वर्ष 2008–09 में प्रारंभ कर पूर्णता तक लाया गया है। इस योजना से 22 हजार 800 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। दुर्ग–राजनांदगांव जिले की 'मोहड़ परियोजना' का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे 800

हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। बस्तर की 'कोसारटेडा सिंचाई परियोजना' में 11 हजार 120 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष 9 हजार 500 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

10. मेरी सरकार ने सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2003 में चिन्हित सभी 72 हजार 329 बसाहटों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय मापदण्ड पूरा कर लिया है। 250 व्यक्तियों के बीच 1 हैण्डपम्प के राष्ट्रीय मापदण्ड के विरुद्ध राज्य में 90 व्यक्तियों के बीच 1 हैण्डपम्प उपलब्ध करा दिया गया है। अब तक स्वीकृत कुल 2 हजार 357 'नल–जल योजनाओं' में से 1 हजार 736 पूर्ण हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 467 स्वीकृत 'स्थल जल प्रदाय योजना' में से 1 हजार 900 पूर्ण हो चुकी हैं, शेष योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है। पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण हेतु निःशुल्क दूरभाष के उपयोग हेतु 'टोल–फ्री नंबर' की सुविधा आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है।

11. मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा की अपनी सुविचारित और पारदर्शी प्रणाली विकसित की है। गौरव का विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ की कम्प्यूटरीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश में आदर्श तथा अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है। 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' के जरिए राज्य की 70 प्रतिशत आबादी को एक रुपए और दो रुपए किलो में चावल तथा 'छत्तीसगढ़ अमृत नमक' का निःशुल्क प्रदाय जारी रखने हेतु मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में 'बीपीएल' व 'अंत्योदय' कार्डधारियों को 5 रुपए किलो में 'चना वितरण योजना' के फायदों को देखते हुए इसका

विस्तार किया जाएगा। केरोसिन वितरण की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। प्रायोगिक तौर पर 'कोर पीडीएस परियोजना' रायपुर शहर से शुरू की जा रही है, जिससे किसी भी दुकान से किसी भी वार्ड के निवासी, सुविधानुसार राशन प्राप्त कर सकेंगे। रायपुर शहर में 50 दुकान सह गोदामों का निर्माण भी शुरू किया गया है, इस योजना का समयबद्ध विस्तार समस्त नगरीय निकायों में किया जाएगा।

12. मुझे खुशी है कि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (मनरेगा) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कोरिया, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर जिलों को तथा दुर्ग जिले की मचान्दुर और खैरवाही ग्राम पंचायतों को केन्द्र द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इस वर्ष यह गौरव सरगुजा जिले को मिला है। पुनर्गठन उपरांत 27 जिलों के नजरिए से देखें तो प्रदेश के आधे से अधिक जिले इस गौरव से जुड़ चुके हैं। 'मनरेगा' से इस वर्ष लगभग 23 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 'मनरेगा' के पारदर्शी और कारगर क्रियान्वयन हेतु ऑनलाइन पंजीयन, मॉनीटरिंग तथा समस्या निवारण के लिए विशेष पोर्टल की व्यवस्था की गई है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 'बिहान' योजना संचालित करने हेतु प्रथम चरण में 30 विकासखण्डों का चयन कर लिया गया है।

13. राज्य में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत 4 हजार 765 करोड़ रूपए की लागत से 19 हजार 236 किलोमीटर लंबाई की 4 हजार 264 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 8 हजार 626 बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के दायरे में नहीं आने वाली बसाहटों के लिए मेरी सरकार 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास

योजना' के माध्यम से 4 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करेगी, तदनुरूप प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

14. ग्रामोद्योग क्षेत्र में नई सुविधाएं जुटाकर भी मेरी सरकार ने गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। बुनाई मजदूरी में 25 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। बुनकरों को हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री से होने वाले लाभ में से 50 प्रतिशत राशि लाभांश के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। ऐसी योजनाओं का लाभ 52 हजार से अधिक बुनकरों को मिलेगा। रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प आदि कार्यों को ज्यादा लाभप्रद बनाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

15. पंचायतों का कामकाज सुचारू रूप से संचालित करने, उनमें पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाया गया है। 97 प्रतिशत से अधिक पंचायतों में 'प्रिया–सॉफ्ट' के माध्यम से 'ऑन–लाइन एकाउंटिंग' की जाने लगी है। इस काम के लिए छत्तीसगढ़ को देश के प्रथम दो राज्यों में सराहा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं जांजगीर–चांपा जिलों में 378 नवीन पंचायत भवनों का निर्माण एवं 202 पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पंचायतों के पास स्वयं के सुविधाजनक भवन हों।

16. मेरी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा पिछड़े क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए नई रणनीतियां अपनाने की पक्षधर है। मैदानी स्तर पर प्रशासकीय आवश्यकताओं और जन सामान्य की सुविधाओं को संतुलित करते हुए जिलों का पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण किया गया है। 9 नए जिलों के निर्माण से राज्य में जिलों की संख्या 18 से बढ़कर 27 हो गई है। जनता ने जिस

अभूतपूर्व उत्साह से नवगठित जिलों का स्वागत किया, वह विकास के प्रति उनकी बढ़ती ललक का परिचायक है। इससे शासन–प्रशासन तथा जनता को नजदीक लाने के प्रयासों की सार्थकता भी दिखाई पड़ती है और योजनाओं को समस्त जिलों में बेहतर ढंग से संचालित करने का एक नया दौर शुरू हुआ है।

17. मेरी सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल उत्तरी क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने के लिए 'रेल कॉरीडोर' के निर्माण की वृहद कार्य योजना बनाई है। प्रथम चरण में लगभग 4 हजार 500 करोड़ रूपए की लागत से 'पब्लिक–प्रायवेट–पार्टनरशिप' के तहत यह कॉरीडोर विकसित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के साथ एमओयू कर रिकार्ड समय में इस अभिनव परियोजना की मजबूत नींव रखी गई है, जिसे केन्द्र शासन ने अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बताया है। इस कॉरीडोर से उत्तरी छत्तीसगढ़ के भूपदेवपुर–घरघोड़ा–धरमजयगढ़–कोरबा–डोंगामहुआ–गारेपलमा, सूरजपुर–परसा–कटघोरा–कोरबा, गेवरा रोड– पेंड्रारोड–दीपका–कटघोरा–सिंदुरगढ़–पसान जैसे स्थान 452 किलो मीटर लम्बे रेल मार्ग से जुड़ेंगे। इस प्रकार 60 वर्षों से रेल परिवहन की सुविधा से वंचित जनता को 60 महीनों में यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

18. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास को भी राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास का आधार माना है। विगत आठ वर्षों में लगभग 25 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन किया गया है। 11 रेलवे ओवर ब्रिज, 910 पुल बनाए गए। आगामी वर्ष में लगभग 1630 किलोमीटर सड़कों, दो रेलवे ओवर ब्रिज तथा 73 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

ठेकेदारों के ऑनलाइन पंजीयन, ई–टेण्डरिंग और लेखों के कम्प्यूटरीकरण से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाई गई है।

19. 'बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण' तथा 'सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण' की कार्य प्रणाली से इन क्षेत्रों में जो विकास और विश्वास बढ़ा है, उसे देखते हुए शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण' का गठन किया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत वर्ष 2011–12 में 257 करोड़ रुपए की लागत से 4 हजार 216 कार्य प्रारंभ किये गए हैं। एकीकृत कार्ययोजना (आई.ए.पी.) के अंतर्गत आने वाले जिलों में 558.36 करोड़ रुपए की लागत से 14 हजार 276 कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिससे स्थानीय अनुसूचित जनजाति आबादी को छोटी लागत और कम समय में पूर्ण होने वाले विकास कार्यों का लाभ मिल रहा है।

20. मेरी सरकार ने मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तार किया है। कोरबा, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा तथा दुर्ग जिला चिकित्सालयों, कुरूद, मनेन्द्रगढ़, खैरागढ़ तथा बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता का आईएसओ 9001–2000 का मानक प्राप्त हो गया है। 67 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24 घंटे खुला रखने की व्यवस्था हो गई है और 190 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शीघ्र यह सुविधा मिल जाएगी।

21. मेरी सरकार की अभिनव योजनाओं के तहत 'मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना' में 1800 से अधिक बच्चों को नवजीवन मिल चुका है। 'मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना' से 100 से अधिक बच्चों के जीवन में नई आशा का संचार हुआ है। 'संजीवनी

सहायता कोष' के अंतर्गत लगभग 39 हजार लोगों को हृदय रोग के उपचार तथा गुर्दा प्रत्यारोपण की मदद मिली है। '108 संजीवनी एक्सप्रेस' का विस्तार पूरे राज्य में करते हुए 172 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं।

22. मेरी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक समस्त उपायों से महिला सशक्तीकरण को बल दिया है। महिला स्व–सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण राशि की अधिकतम सीमा प्रथम बार के लिए 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए तथा द्वितीय बार हेतु 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है। 28 हजार 583 आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वयं के भवनों की सौगात दी गई है। कुपोषण दूर करने के लिए शासन–समाज की सहभागिता से नई योजना 'नवा जतन' शुरू की गई है। इस योजना में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाली पंचायतों एवं समूहों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ की नारियां अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान दर्ज होने लगा है।

23. राज्य के विकास में मेरी सरकार ने एक ओर जहां जनता के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर सबकी बेहतरी का भी ध्यान रखा है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम अंग, उपकरण निर्माण हेतु 'फिजिकल रिहेबिलिटेशन रिफरल सेन्टर' की स्थापना की जा रही है। बौने व्यक्तियों को निःशक्तजनों की भांति आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है।

24. मेरी सरकार विभिन्न नगरों में सुधारों का सिलसिला जारी रखने के लिए पृथक–पृथक नगर विकास योजनाएं बनाकर उन्हें साकार कर रही है। शहरों का वातावरण सुखद बनाने हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सड़क, नाली, सड़क बत्ती, पेयजल, सामुदायिक भवन, गौरव पथ, प्रवेश द्वार, तालाबों, चौराहों और उद्यानों का सौन्दर्यीकरण, शालाओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक प्रसाधनों का निर्माण, बाजारों का विकास, बेरोजगारों तथा महिलाओं के लिए विशेष बाजारों का निर्माण जैसे कार्यों के लिए विगत सिर्फ एक वर्ष में 1 हजार 4 सौ 41 करोड़ रुपए का अनुदान नगरीय निकायों को दिया गया है।

25. शहरों की तंग बस्तियों के रहवासी गरीब परिवारों की महिलाओं को सड़कों पर आकर पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई भागीरथी नल–जल योजना के तहत 99 निकायों में 1 लाख 20 हजार परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शनों की स्वीकृति दी गई है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने का गौरव भी मिला है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को 'री–सायकल' करने में मदद करने वाले गरीबजन वास्तव में शहरों की सड़कों से कांच, प्लास्टिक, कागज, लोहा आदि बीन कर गुजारा करते हैं, इनकी मदद हेतु 'रेगपिकर्स कल्याण योजना' शुरू की गई है।

26. मेरी सरकार ने राज्य में आवास की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रत्येक आय वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं। विगत छः वर्षों में 'छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल' द्वारा लगभग 60 हजार आवासों के निर्माण का बीड़ा उठाया गया है। छोटे नगरों और कस्बों में सुनियोजित शहरी विकास तथा आवास

सुविधाएं विकसित करने के लिए 11 हजार 800 करोड़ रुपए की लागत से 'अटल विहार योजना' इस वर्ष प्रारंभ की गई है। 100 से 150 स्थानों में इस योजना के संचालन हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को 80 हजार रुपए तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को 40 हजार रुपए प्रति हितग्राही के मान से, इस तरह 45 हजार जरूरतमंद परिवारों को 240 करोड़ रुपए के अनुदान का लाभ मिल सकेगा।

27. राज्य के स्वाभिमान, संस्कारों और संभावनाओं का प्रतीक बन रहे 'नया रायपुर' में नई प्रशासनिक राजधानी तेजी से आकार ले रही है। राज्य का मंत्रालय शीघ्र ही नया रायपुर में स्थानांतरित करने की तैयारी प्रगति पर है। राज्य की संस्कृति और धरोहरों को सहेजा जा रहा है, वहीं प्रचलित लोक पर्वों–लोकोत्सवों को नए सिरे से रेखांकित करते हुए उन्हें व्यापक महत्व प्रदान किया जा रहा है। सिरपुर, सिली पचराही, मदकू द्वीप में पुरातत्वीय उत्खनन से राज्य के पुरावैभव के नए प्रमाण मिल रहे हैं। राजिम कुंभ की महिमा का साल–दर–साल विस्तार किया जा रहा है।

28. मेरी सरकार ने एक ओर जहां खनिज सम्पदा के राज्य में ही मूल्य संवर्धन (वेल्यू एडीशन) की रणनीति अपनाई है, वहीं नवीन औद्योगिक नीति के तहत जिले के स्थान पर विकासखण्डों को औद्योगिक विकास का केन्द्र बनाया गया है। अब राज्य में उद्योगों का विस्तार नए स्थानों पर हो रहा है, जिससे विकास के क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य में स्टील, सीमेंट, ऊर्जा तथा एल्युमीनियम आदि परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न उद्योग समूहों द्वारा लगभग 30 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है और 58 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।

29. मेरी सरकार की सतत जागरूकता, सूझबूझ और सुसंगत प्रयासों के कारण देशव्यापी बिजली संकट के असर से छत्तीसगढ़ अछूता रहा है। राज्य क्षेत्र में 250 मेगावॉट क्षमता के बिजली घर स्थापित किए जा चुके हैं तथा 1500 मेगावॉट क्षमता के बिजली घर आगामी एक वर्ष में शुरू करने का लक्ष्य है। निजी क्षेत्र में 4 हजार मेगावॉट क्षमता के बिजली घर लगाने की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है। केन्द्रीय क्षेत्र में 4 हजार मेगावॉट क्षमता का बिजली घर भी शीघ्र प्रारंभ करने की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 50 प्रतिशत बिजली मिलना सुनिश्चित किया गया है।

30. बिजली उत्पादन की तरह उसके पारेषण और वितरण पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से पारेषण, वितरण नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिसके कारण राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और लो–वोल्टेज की समस्याओं का निदान हुआ है। उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. से देयक की जानकारी देने व 'स्पॉट बिलिंग' सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

31. मेरी सरकार ने विद्युत विकास को सामाजिक–आर्थिक बदलाव का एक बड़ा माध्यम बनाया है। आजादी के बाद 57 वर्षों में सिर्फ 72 हजार पम्प कनेक्शन किसानों को दिए गए थे, जबकि विगत 8 वर्षों में लगभग 2 लाख 20 हजार नए सिंचाई पम्प कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को उनके पांच हार्स पॉवर तक के पम्पों पर 6 हजार यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदाय की सुविधा जारी रखी गई है।

32. सरकारी काम–काज में पारदर्शिता और कसावट लाने के लिए 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011' लागू किया गया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली लोक सेवाएं एक निर्धारित समय सीमा में जनता को दी जाएंगी। नियत समय सीमा में सेवा न मिलने पर जनता परिव्यय पाने की हकदार हो जाएगी। विभिन्न विभागों की 251 लोक सेवाएं इस अधिनियम के दायरे में लाई गई हैं।

33. मेरी सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के यथोचित उपयोग पर बल दिया है। देश में अपनी तरह की अभिनव 'स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क' (स्वॉन) परियोजना का काम छत्तीसगढ़ में पूर्ण किया जा चुका है। इससे 3 हजार 500 कार्यालय जोड़े गए हैं। शहरों–कस्बों में लगभग 3 हजार 'चॉइस केन्द्र' अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 'ई–प्रोक्योरमेंट' परियोजना ने पारदर्शिता तथा कार्य दक्षता बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। 21 विभागों में लगभग 29 हजार करोड़ रुपए की निविदाओं की ऑनलाइन प्रोसेसिंग की जा रही है। 'राज्य डेटा सेंटर' का निर्माण पूर्णता की ओर है। 'इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे' का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का गौरव छत्तीसगढ़ को मिला है। राज्य का 'स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे' और 'स्टेट पोर्टल' भी शीघ्र ही प्रारंभ करने की योजना है।

34. प्रदेश में व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण रियायतें एवं सुविधाएं दी गई हैं। इस वर्ष 40 लाख रूपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए 'स्व–कर निर्धारण' की समय सीमा बढ़ाई गई है। इंस्पेक्टर राज

समाप्त करने के लिए विक्रय कर जांच चौकियों को समाप्त किया गया है। इस वर्ष पंजीयन, सी–फार्म, ई–पेमेंट एवं ई–रिटर्न की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

35. 'ई–प्रशासन' की सुविधाएं अनेक नए क्षेत्रों में लागू की गई हैं। राज्य के सभी कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण कर नेटवर्किंग की गई है। 'ई–कोष' योजना से कर्मचारियों से संबंधित समस्त वित्तीय जानकारियों का संधारण किया जा रहा है। साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। 'ई–चालान' योजना के माध्यम से कोई व्यक्ति घर बैठे चालान जमा करने की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

36. मेरी सरकार मदिरापान की बुराइयों के खिलाफ वातावरण बनाने, जनजागरण करने और उसमें सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 'भारतमाता वाहिनी' का गठन कर रही है। इस वर्ष 7 जिलों के 15 विकासखण्डों की 75 ग्राम पंचायतों में वाहिनियां गठित कर दी गई हैं। क्रमशः इनका विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। वर्ष 2011 में 2 हजार से कम जनसंख्या के गांवों में स्थित 239 शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। आगामी वर्ष में 2 हजार 500 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में 84 शराब दुकानों को बंद किया जा रहा है।

37. मेरी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में स्थायित्व तथा सुरक्षा की भावना भरने हेतु 40 प्रकार के श्रमिकों को अधिसूचित कर उन्हें श्रम प्रावधानों का लाभ दिला रही है। ठेका श्रमिकों को चैक के माध्यम से वेतन तथा परिचय पत्र प्रदान किया जा रहा है। 'असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल' का गठन किया गया है। 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल' का गठन कर इसके माध्यम से 1 लाख 30 हजार से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

विभिन्न श्रमिकों के कल्याण हेतु लगभग दो दर्जन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

38. मेरी सरकार ने वनों के प्रबंधन में वैज्ञानिक तरीकों और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। सरगुजा जिले के दूरस्थ वनांचलों में ग्रामीणों तथा उनकी फसलों को हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए 300 किलोमीटर क्षेत्र में 'सोलर पॉवर्ड फेन्सिंग' कराई गई है। राज्य के उत्तरी भाग में हाथियों की अधिकता को देखते हुए बादलखोल, तमोरपिंगला एवं सेमरसोत अभयारण्यों को 'हाथी रिजर्व क्षेत्र' घोषित किया गया है। प्रदेश के 32 में से 31 वन मण्डल में वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत कार्य आयोजनाएं प्रभावशील हैं। 7 हजार 887 'वन प्रबंधन समितियों' का गठन कर, उन्हें 35 हजार 190 वर्ग किलोमीटर वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समितियों को वनोपज के कारोबार के हिस्से के रूप में 16 करोड़ रुपए की राशि इस वर्ष दी जा रही है।

39. 'कैम्पा योजना' के तहत इस वर्ष संरक्षित क्षेत्रों में स्थित गांवों के अन्यत्र विस्थापन, नदी तट वृक्षारोपण, शहरों में ऑक्सीवन रोपण, प्राकृतिक पुनरोत्पादन में मदद, क्षतिपूर्ति वनीकरण जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। 'बांस मिशन' के अंतर्गत 1300 हेक्टेयर में इस वर्ष बांस रोपण किया गया है, वहीं विगत 3 वर्षों में 28 बांस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

40. आजीविका के लिए वनों पर आश्रित लोगों के लिए मेरी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ाते हुए इस वर्ष 700 रुपए प्रति मानक बोरा से 800 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। करीब 14 लाख संग्राहकों को लगभग 109 करोड़

रुपए की संग्रहण मजदूरी और विगत वर्ष के कारोबार से 138 करोड़ रुपए का बोनस प्रदान किया गया है। ऐसे समस्त परिवारों को 'जनश्री बीमा योजना' का लाभ दिया जा रहा है।

41. मेरी सरकार चाहती है कि राज्य में शिक्षा के लोकव्यापीकरण का काम जमीनी हकीकत का रूप ले। इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 98 प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया गया। विपरीत परिस्थितियों वाले लगभग 1 लाख 28 हजार शाला अप्रवेशी बच्चों में से 96 हजार को आवासीय–गैरआवासीय पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया है।

42. मेरी सरकार पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं के लिए 1 लाख 45 हजार शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। इन्हें सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत), व्याख्याता (पंचायत) का नया पदनाम दिया गया है। इस संवर्ग को स्थानांतरण नीति, अंशदायी पेंशन योजना, अनुकम्पा नियुक्ति, अनुग्रह राशि, क्रमोन्नति वेतनमान जैसी तमाम सुविधाओं के आदेश जारी किये गये हैं। राज्य स्तर पर आयोजित 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' के माध्यम से 77 हजार से अधिक युवाओं को शिक्षकीय कार्य के लिए पात्रता और मान्यता प्रदान की गई है।

43. राज्य में लगभग 1 लाख 75 हजार अध्यापकों को विभिन्न स्तरों का प्रशिक्षण दिया गया है। इस वर्ष 193 प्राथमिक, 140 उच्च प्राथमिक, 1 हजार 133 हाईस्कूल, 101 हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा 17 नाइट शेल्टर स्कूल शुरु किए गए हैं। 8 हजार से अधिक शालाओं का विद्युतीकरण किया गया और लगभग 27 हजार शालाओं में रैम्प बनाए गए हैं। शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त लगभग 48 हजार प्राथमिक शालाओं के 40 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। सभी बच्चों को

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जा रही हैं। 'बीपीएल' परिवारों की हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें दी जा रही हैं। विभिन्न प्रयासों का लाभ 'ड्रॉप–आउट' दर कम करने में मिला है। मुझे खुशी है कि विगत दशक में साक्षरता की दर में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे कुल साक्षरता 71.04 प्रतिशत हो गई है। 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के माध्यम से राज्य में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की शुरुआत वर्ष 2009–10 में की गई थी, जिसके तहत तीन वर्षों में 1 हजार 342 नवीन माध्यमिक शालाओं का संचालन बेहतर भवनों, शिक्षकों तथा नवाचार की सुविधाओं के साथ किया जा रहा है।

44. उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने शासकीय विश्वविद्यालय की संख्या तीन से बढ़ाकर सात कर दी है। बिलासपुर में एक नवीन विश्वविद्यालय आगामी सत्र से शुरू किया जा रहा है। राज्य गठन के बाद नव स्थापित 56 महाविद्यालयों में से 33 शासकीय महाविद्यालय दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों में खोले गए हैं।

45. तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए मेरी सरकार ने प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश क्षमता 2 हजार 730 से बढ़ाकर 19 हजार 590 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 1 हजार 495 से बढ़ाकर 3 हजार 840 तक पहुंचा दी है। अब इन संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

46. युवाओं को पढ़ाई के साथ खेल–कूद में भी कैरियर निर्माण के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न खेल–सुविधाओं में वृद्धि की है। राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 58 स्वर्ण, 54 रजत और 33 कांस्य

पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक समूहों को 33 खेलों को गोद लेने हेतु प्रेरित किया गया है, ताकि वे संबंधित सुविधाएं और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं कर सकें। अपना वादा निभाते हुए राज्य सरकार ने 25 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी है।

47. मेरी सरकार ने राज्य के विकास के बढ़ते कदमों में युवाओं और बेरोजगारों को सीधी भागीदारी दी है। शासन के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति में लगे प्रतिबंध हटाए गए हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों को जिला काडर मानकर स्थानीय निवासियों से भरे जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं की भर्ती हेतु अभियान छेड़ा गया है, इसके लिए हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे एक वर्ष में लगभग 12 हजार लोगों को रोजगार मिला। युवाओं को पंजीयन, नवीनीकरण, योग्यता वृद्धि जैसे कार्य ऑनलाईन करने की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आगामी 'प्रारंभिक परीक्षा' के लिए पूर्व मार्गदर्शन की व्यवस्था भी राज्य में पहली बार की गई है।

48. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में सदैव आगे रही है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुविधा देने हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग को राज्य स्तर पर सभी श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों में 32 प्रतिशत आरक्षण देने, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14

प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के कुल बजट में से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक बजट प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है, जो राज्य शासन की प्राथमिकता की मिसाल है। इन तबकों के लिए शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। आवश्यकताओं की विविधता को देखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं।

49. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित 3 हजार से अधिक छात्रावासों तथा आश्रमों में रहकर पढ़ रहे लगभग एक लाख 60 हजार बच्चों की शिष्यवृत्ति 450 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए प्रतिमाह की गई है। जनश्री बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश प्रदाय योजना, विशेष कोचिंग योजना, छात्रावास–आश्रम शाला योजना, आगमन भत्ता योजना, भोजन सहाय योजना, स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना, राहत योजना, सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना, राज्य छात्रवृत्ति योजना, एयर होस्टेस–पायलट प्रशिक्षण योजना, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, रविदास चर्मशिल्प योजना, नर्सिंग पाठ्यक्रम योजना आदि का प्रभाव इन तबकों में दिखने लगा है। इन योजनाओं से लाभान्वित बच्चों का चयन आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसी संस्थाओं में हो रहा है, जो सुखद संकेत है।

50. मेरी सरकार न्याय व्यवस्था की मजबूती हेतु भी आवश्यक उपाय कर रही है। केन्द्र द्वारा संचालित 31 'फास्ट–ट्रेक कोर्ट' की व्यवस्था समाप्त किए जाने से उत्पन्न रिक्तता की भरपाई हेतु

राज्य स्तर पर प्रथम चरण में 11 स्थानों पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय खोले जा रहे हैं।

51. मेरी सरकार ने प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के सफर में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा है। यही वजह है कि सीमावर्ती जिलों में नक्सलवादी विध्वंस और उनकी विकास विरोधी गतिविधियों के बावजूद राज्य में विकास का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। शासन–प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य में शांति और व्यवस्था का बेहतर वातावरण बनाए रखने के लिए मेरी सरकार सतत प्रयासरत है। विगत सिर्फ एक वर्ष में पुलिस विभाग में 12 हजार से अधिक पदों का सृजन किया गया है। राज्य गठन के समय पुलिस बलों की संख्या 22 हजार 564 थी, जो अब बढ़कर 64 हजार से अधिक हो गई है। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष भत्ता, आवास, पुनर्वास, बीमा सुविधा जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का काम संवेदनशीलता के साथ किया गया है।

52. मेरी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से राज्य के युवा वर्ग में उत्साह का अद्‌भुत संचार हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभाएं उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते दिखने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के जवानों की सेना में भर्ती के लिए कमतर रूचि का मिथक भी अब टूटने लगा है। युवाओं ने यह साबित किया है कि यदि उन्हें अवसर तथा सूचनाएं मिलें तो वे हर क्षेत्र में कुछ बेहतर कर गुजरने को तैयार हैं। हाल ही में बस्तर में आयोजित सेना की भर्ती रैली में प्रदेश से कुल 161 जवानों का चयन हुआ है, जिनमें से 121 बस्तर के हैं। यह सफलता साबित करती है कि सही

दिशा में किए जा रहे सही प्रयासों से राज्य की तरुणाई का हौसला बढ़ रहा है।

53. नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों का संचालन सचमुच चुनौतीपूर्ण है। जनता का विश्वास जीतकर ही विध्वंसकारियों की नापाक हरकतों पर विराम लगाया जा सकता है। मेरी सरकार ने आप सबके सहयोग से संवैधानिक व्यवस्थाओं में जन–साधारण की आस्था बनाये रखने और बढ़ाने के लिए विध्वंस के बीच भी निर्माण की चुनौती स्वीकार की है। शांति के साथ विकास के प्रयास सतत जारी रखे जाएंगे, जिससे राज्य के समग्र विकास में हर क्षेत्र, अपनी संपूर्ण क्षमता से अपना योगदान दर्ज कर सकें। छत्तीसगढ़ को विकास का गढ़ बनाने का सपना जरूर पूरा होगा।

जय हिन्द

जय छत्तीसगढ़